Pension to 60,000 MTNL Employees of Mumbai and Delhi

SHRI BHARAT KUMAR BHAVANISHANKAR RAUT (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, I wish to give voice to the long-pending grievance of 34,000 employees of MTNL working in Delhi and Mumbai. Sir, these employees are up in arms. They are agitating and protesting for fulfilment of their demand which is their natural right. If getting Government pension is a right, then, these 34,000 employees have been deprived of their natural right; their democratic right for the last so many years. It is not that they have been just sitting with folded hands. This story goes way back to 1986 when MTNL was launched with a great fanfare. At that time, all these employees who were working for DoT were transferred on deputation to MTNL in Mumbai and Delhi. It is not that it was their choice. By force and obligation, all these employees were shifted to MTNL and from then on they have been deprived of their right to get Government pension. After that, those employees were absorbed in the MTNL. The assurance given by the Government was that all the rights and benefits of being a Government servant would be transferred to these employees working in PSUs also. But it has not happened. The employees have been demanding for this. In 2002, the then Minister for Communications, Mr. Pramod Mahajan, held a meeting and he assured that Government pension will be given to the MTNL employees. But, nothing happened. After that, the leader of my Party, Shri Manohar Joshi, who was the Speaker of the Lok Sabha, took initiative and held meeting. Again, an assurance was given that Government pension and family pension will be given. Nothing happened after that. Sir, the employees kept agitating, and now in December, again, a delegation of these employees met the Minister, Mr. Raja. He assured them that the required notification will be issued. Sir, 34,000 employees are waiting for justice. Today, outside this House, in Delhi, 15,000 employees have assembled to demand for Government pension. We say that we are in the era of communication. Telephone has been our lifeline. And, particularly, for people living in Mumbai and Delhi, it is a right. Why are you not allowing their right to life? I think the Minister should immediately take it up and do justice to them. Thank you,

Incidents of dog bites in Delhi and non-availability of anti-rabies vaccine

श्री शाहिद सिदीकी: (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद महोदय, आज हमारे मुल्क के गावों में, गालियों में, बाज़ारों में, शहरों में और खास तौर से बड़े शहरों में एक आतंक फैला हुआ है। वह आंतक बहुत खतरनाक है और आम आदमी को इस आंतक का सामना करना पड़ रहा है। वह आतंक है—जो लाखों की तादात में कृत्ते गलियों में घूम रहे हैं। वे आम आदमी पर इस तरह से हमला करते हैं। वह आम आदमी सड़कों पर निकलता है, वह गाडियों में नहीं घूम सकता। उससे भी बडी दिक्कत यह है कि वैक्सीन अस्पतालों में अवेलेबल नहीं है। आज ही के अखबार में यह खबर है कि एक बच्चे को कृत्ते ने काट लिया। उसे 6 अस्पालों में ले गए। हर जगह यह कहा गया कि हमारे पास खबर है कि एक बच्चे को कृत्ते ने काट लिया। उसे 6 अस्पतालों में ले गए। हर जगह यह कहा गया है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है और आप हमारे एरिया में नहीं आते। जैसे पुलिस स्टेशन का एरिया होता है उसी तरह अस्पतालों का एरिया कर दिया गया है। आपको मालूम है कि अगर 24 घंटे के अंदर-अदंर वेक्सीन नहीं लगे तो आदमी मारा जाएगा। ज्यादातर औरते और बच्चे ही कृतों के काटने का शिकार हो रहे हैं। यह बंगलीर में बहुत ही बड़ा मसला है, मुम्बई में शायद इतना नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में, बंगलौर में, छोटे-छोटे कस्बों में इनका एक आतंक फैसला हुआ है। इस कारण सुबह को बुढे लोग वॉक पर नहीं जा सकते। वॉक करने जाते हैं तो कृत्ते उन पर हमला कर देते हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक तो आप वेक्सी न का इंतजाम कीजिए और यह जो वेक्सीनेशन का एरिया बांट दिया गया है, यह बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें आपको टाइम बाउंड वेक्सीनेशन चाहिए होता है। आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में इसकी खबर है कि अस्पताल में नहीं होने की वजह से एक बच्चे को वेक्सीन नहीं मिला। यह मसला आज का नहीं है, मुसलसल में देख रहा हूँ, जब हम अपनी कंस्टीट्यूंसी में जाते हैं तो हमे वहां लोगों से यह शिकायत मिलती है। यह मसला बहुत छोटा है, इसलिए यह मसला इतने बड़े हाउस में उठाने का नहीं है। लेकिन आम आदमी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित